

मामलों का विवरण

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बनाम.

एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑर्स। (सी. ए. No.8378/2018 में विविध अनुप्रयोग No.1721/2023) 04 दिसंबर, 2023

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:अक्षर dtd.24.05 का प्रभाव।2011 हाइपोथेटिकल रेगुलेटरी एसेट बेस (एच. आर. ए. बी.) की गणना में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत।जैसा कि अनुरोध किया गया था, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड बनाम भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण में निर्णय कि क्या संशोधित किया जाना है या मामले को टीडीएसएटी को प्रेषित किया जाना है ताकि एचआरएबी की सीमित निर्गम के लिए उपरोक्त पत्र के प्रभाव की जांच की जा सके।

काल्पनिक नियामक परिसंपत्ति आधार (एच. आर. ए. बी.) की गणना-अक्षर **dtd.24.05** का प्रभाव।**2011** - एच. आर. ए. बी. की गणना के संबंध में विवाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड बनाम भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण में दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि **[2022] 11 एस. सी. आर. 869**-भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ए. ई. आर. ए.) और टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इस अदालत का अभेद्य है-अब, एक आंतरिक पत्राचार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ए. ई. आर. ए. के बीच दिनांकित एक पत्र आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त निर्णय में रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि को जन्म दिया गया है-आवेदकों की याचिका अन्य बातों के साथ-साथ कि पत्र बैंक सोल्विंग की विधि द्वारा एच. आर. ए. बी. की गणना के मुख्य मुद्दे से संबंधित है और इस अदालत ने अपने निष्कर्ष को "वैमानिकी सेवाओं से संबंधित" अभिव्यक्ति तक सीमित कर दिया था।

802

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बनाम.एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑर्स।

डी. टी. डी. पत्र के प्रभाव की जांच करें।**24.05.2011** एच. आर. ए. बी. की सीमित निर्गम गणना के लिए:

आयोजित किया गया:इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति दो विशेषज्ञ प्राधिकरणों/न्यायाधिकरणों पर आधारित है जिन्होंने इस पर अपना दिमाग लगाया है-सबूतों और तथ्यों की फिर से सराहना करना मुश्किल होगा, विशेष रूप से जब टीडीएसएटी ने इस पर राय नहीं दी है-इस पहलू में उद्यम करना उचित नहीं है-हालांकि, पत्र गैर-आवेदकों के लिए एक आंतरिक संचार की प्रकृति में होने के कारण, संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाना चाहिए था-इस स्तर

पर यह कहना मुश्किल होगा कि इसका कोई प्रभाव है या नहीं, जब तक कि टीडीएसएटी की राय उपलब्ध नहीं है-इस दस्तावेज़ की जांच टीडीएसएटी द्वारा की जानी है-टीडीएसएटी एच की सीमित मुद्दे की गणना के लिए कर सकता है। 24.05.2011, और एच. आर. ए. बी. की गणना में इसके प्रभाव पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखें और क्या 'सिंगल टिल' तंत्र गणना का आधार होना चाहिए। [पैरा 14,15]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2018 की सिविल अपील संख्या 8378 में 2023 का विविध आवेदन No.1721।

2012 के ए. ई. आर. ए. अपील सं. 10 में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 23.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2019 के सी. ए. No.5401 में 2023 का विविध आवेदन संख्या 1710।

रूप:

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, साजन पूवय्या, विपिन सांघी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मिलिंद चौधरी, सुश्री नैना दुबे, आलोक त्रिपाठी, महेश अग्रवाल, सुश्री अमृता नारायण, मनु कृष्णन, मोहित डी. राम, अश्विन राकेश, अभिषेक कक्कड़, अर्शित, अनुभव शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अपूर्व कुरूप, प्रणय रंजन, ऋत्विज ऋषभ, दुर्गा दत्त, सार्थक करोल, सुश्री योग्या राजपुरोहित, अमरीश कुमार, सचिन

804

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

शर्मा, अनिल कुमार गुलाटी, सुश्री नूर टंडन, नमन शर्मा, कुणाल जिंदिया, चित्रन सिंघल, शेवा भारती, यशोधरा बर्मन राँय, रितेश कुमार, सुश्री नीलम राठौर, शुभम सेठ, अनुज पंवार, निकलेश रामचंद्रन, बडी रंगनाथन, सुश्री निष्ठा कुमार, प्रंतर बसु चौधरी, साहिल टागोत्रा, अर्जुन महाजन, सुमित आर. शर्मा, राघवेंद्र बुधोलिया, पीयूष गौतम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश संजय किशन कौल, जे।

1. हमने सोचा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमारा फैसला

लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण **1**

सभी समस्याओं का समाधान करें। ऐसा प्रतीत नहीं होता। 2. आवेदनों का नेतृत्व दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डी. आई. ए. एल.) और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एम. आई. ए. एल.) दोनों ने किया है, जो एक 'नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य' की खोज पर आधारित है, जो उचित परिश्रम करने के बाद भी आवेदकों की जानकारी में नहीं था। आवेदकों ने 24.05.2011 दिनांकित एक पत्र का उल्लेख किया है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय (संक्षेप में 'एमओसीए') और हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संक्षेप में 'ईआरए') के बीच एक आंतरिक पत्राचार है, जिसमें कहा गया है कि "तदनुसार, इस मामले में प्रस्तावित दृष्टिकोण वैमानिकी शुल्क को देखते हुए प्रारंभिक वैमानिकी परिसंपत्ति आधार को हल करने के लिए है। राज्य सहायता समझौते में, अनुसूची-I में पहली नियामक अवधि के लिए परिसंपत्ति आधार की गणना करने की विधि की अवहेलना की गई है।"

3. कहा जाता है कि उपरोक्त ने निर्णय के पैरा 50 और 63 में अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि को जन्म दिया है।

4. यदि हम "काल्पनिक विनियामक परिसंपत्ति आधार (एच. आर. ए. बी.) की गणना" शीर्षक के तहत अपने फैसले की ओर मुड़ते हैं, तो हम इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि विचाराधीन दो हवाई अड्डों को नए सिरे से स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि मौजूदा हवाई अड्डों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। नतीजतन, परिसंपत्तियों में रिफिल के रूप में बाहर निकला

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 850।

805

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बनाम. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे.] 806

लेखा पुस्तकें मूल्यहास को दर्ज करेंगी। इसने पहली नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए विनियामक आधार के मूल्य पर पहुंचने में कठिनाई पैदा कर दी थी। इसके अलावा, पूरे भारत में कई हवाई अड्डों के लिए परिसंपत्तियों की एक साझा सूची थी। इस प्रकार, राज्य समर्थन समझौता (संक्षेप में 'एसएसए') एच. आर. ए. बी. को पीछे की ओर काम करके प्राप्त करने के लिए प्रदान करता है, जिसमें लगातार वर्षों के लिए एक व्यापक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह महत्वपूर्ण था। विचाराधीन सूत्र में इसका मतलब यह होगा कि 'आरबी' शब्द को परिभाषित किया गया है, इस प्रकार, आरबी0 के लिए आधार गणना का आरबी1 की गणना पर और आगे के वर्षों के लिए प्रभाव पड़ेगा। एच. आर. ए. बी. को आरबी0 का निर्धारण करना था।

5. निर्णय के पैरा 50 में, एच. आर. ए. बी. के संबंध में विवाद निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने ए. ई. आर. ए. और टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पैरा 63 में अपनी अभेद्यता दी।

6. आवेदकों की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि एम. ओ. सी. ए. का दिनांकित 24.5.2011 पत्र बैंक सॉल्विंग की विधि द्वारा एच. आर. ए. बी. की गणना के मुख्य मुद्दे से संबंधित है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम पहले से ही कैस्केडिंग एफ. ई. एफ. ई. टी. को पहचान चुके हैं। सवाल यह था कि क्या एसएसए दिनांकित 24.06.2006 के संदर्भ में, एचआरएबी की सही गणना की गई है।

7. प्रभावी रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने "वैमानिकी सेवाओं से संबंधित" अभिव्यक्ति को अपना अधिकार माना है, लेकिन 'एकल टिल' के पहलू पर विचार नहीं किया गया है और एचआरएबी की गणना 'एकल टिल' तंत्र के आधार पर की जानी चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि इस पहलू पर टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा भी विचार नहीं किया गया था। यह कहना उचित होगा कि यह न्यायालय टी. डी. एस. ए. टी. की राय के आधार पर आगे बढ़ा और टी. डी. एस. ए. टी. की राय के दायरे से आगे नहीं बढ़ा।

8. वास्तव में, आवेदकों की ओर से तर्क यह है कि 'सिंगल टिल' तंत्र वर्ष 2008-09 में प्रचलित था, जहां वैमानिकी और गैर-वैमानिकी राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं था और पूरे राजस्व, यानी वैमानिकी और गैर-वैमानिकी को समग्र राजस्व माना जाता था और शुल्क को लागत-प्लस के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2009-10 के लिए एच. आर. ए. बी. की शुरुआत का निर्धारण करने के लिए, पिछले वर्ष के पूरे राजस्व, यानी 2008-09 पर विचार किया जाना चाहिए था।

9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 18.06.2018 दिनांकित एक पत्र का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि "हवाई अड्डे के शुल्क को लागत वसूली सिद्धांत पर निर्धारित किया गया था। लेकिन सभी वैमानिकी के लिए अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

हवाई अड्डों के संचालन से इसके संचालन में उपार्जित गैर-वैमानिकी राजस्व से राजस्व और योगदान।" इसे एसएसए की अनुसूची 1 के प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, और प्रस्तुतिकरण यह है कि "विनियामक आधार के मूल्य की गणना करने के लिए 01.04.2008 और 31.03.2009, यानी, वैमानिकी और गैर-वैमानिकी आय के बीच की अवधि के लिए पूरे राजस्व पर काल्पनिक विनियामक आधार की गणना की जाएगी।" 10. एक वैमानिकी सेवा के रूप में ईंधन प्रवाह शुल्क (एफ. टी. सी.) के वर्गीकरण के लिए कुछ आधार भी उठाए गए हैं।

11. एच. आर. ए. बी. की गणना पर नए सिरे से विचार करने के सीमित मुद्दे के लिए या तो निर्णय को संशोधित करने या मामले को टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष भेजने के लिए अनुरोध किया जाता है।

12. जवाब में, यह कहा गया है कि एफ. टी. सी. से संबंधित मुद्दा अब पैरा 41 से 45 में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए एकीकृत नहीं है। जहाँ तक एच. आर. ए. बी. के मुद्दे का संबंध है, यह पत्र जिसे "नया सबूत" माना जाता है, केवल एक स्पष्टीकरणात्मक संचार है। एम. ओ. सी. ए. ने

बाद में इस मुद्दे को स्पष्ट किया कि कोई भी तंत्र प्रदान करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है और केवल वही उद्धृत किया है जो एस. एस. ए. और ए. बी. एन. ए. एम. आर. ओ. रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

13. शेष उत्तर समझौतों के खंडों के विवरण और व्याख्या से संबंधित है।

14. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति दो विशेषज्ञ प्राधिकरणों/न्यायाधिकरणों पर आधारित है जिन्होंने इस पर अपना दिमाग लगाया है। सबूतों और तथ्यों की फिर से सराहना करना मुश्किल होगा, खासकर जब स्वीकार की गई स्थिति यह है कि टी. डी. एस. ए. टी. ने इस पर राय नहीं दी है। इस प्रकार इस पहलू में उद्यम करना उचित नहीं होगा। हालाँकि, यह पत्र गैर-आवेदनकर्ताओं के लिए एक आंतरिक संचार की प्रकृति में है, हमारा मानना है कि इसे संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाना चाहिए था। चाहे इसका कोई प्रभाव पड़े या न पड़े, टीडीएसएटी की राय उपलब्ध होने तक इस स्तर पर यह कहना हमारे लिए मुश्किल होगा।

15. इस प्रकार, हम यह निर्देश देकर आवेदकों की वैकल्पिक प्रार्थना को अपनाने के लिए इच्छुक हैं कि इस दस्तावेज़ के प्रभाव की जांच टीडीएसएटी द्वारा की जानी चाहिए। हम इस पर विचार करने के लिए इसे टी. डी. एस. ए. टी. पर छोड़ देते हैं, इस तथ्य से अप्रभावित कि टी. डी. एस. ए. टी. की पिछली राय 807 है।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बनाम. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड ऑर्स। [संजय किशन कौल, जे।]

हमारी अभिरुचि प्राप्त की। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. एच. आर. ए. बी. की सीमित अंक की गणना के लिए अब हमारे समक्ष प्रस्तुत पत्र के प्रभाव की जांच कर सकता है, यानी, एम. ओ. सी. ए. द्वारा ए. ई. आर. ए. को दिनांकित पत्र, और एच. आर. ए. बी. की गणना में इसके प्रभाव पर अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण ले सकता है और क्या 'सिंगल टिल' तंत्र गणना का आधार होना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी स्थिति में प्रभावी पक्षों के पास इस न्यायालय के समक्ष एक उपाय होगा।

16. हम उपरोक्त शर्तों में आवेदनों का निपटान करते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

आवेदनों का निपटारा कर दिया गया।

दिव्या पांडे